

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- सामान्य / 15 / 80-81 / 31174-274 दिनांक:- 17/8/89

- 1- समस्त अधीक्षक, उपाधीक्षक एवं प्रभाराधिकारी,
केन्द्रीय / जिला / उप कारागृह, राजस्थान
- 2- उपाधीक्षक,
महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर एवं जोधपुर।

विषय:- बंदियों की निजी सम्पत्ति जेलों में पड़ी हुई है, के निस्तारण के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमांक सामान्य / 15 / 80-81 / 11326-426 दिनांक 30.4.98, क्रमांक 17649-771 दिनांक 8.8.80 एवं 7750-832 दिनांक 12.3.90

—000—

आपको संदर्भित मामलों में कारागृहों एवं उप कारागृहों से रिहा हुए बंदियों की निजी सम्पत्ति के निस्तारण के संबंध में इस कार्यालय के प्रासंगिक परिपत्रों द्वारा समय-समय पर निर्देश प्रदान किये गये हैं।

प्रासंगिक परिपत्रों की एक-एक प्रति पुनः इस परिपत्र के साथ सलग्न कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि कारागृहों से रिहा हुए बंदियों की निजी सम्पत्ति का निस्तारण इस कार्यालय परिपत्र दिनांक 8.8.80 के अनुसार तीन माह में करावे तथा भविष्य में बंदियों की निजी सम्पत्ति उनके कारागृह से रिहा होते समय आवश्यक रूप से लौटाये जाने का ध्यान रखा जावे।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार



महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- प्रभारी, लेखा शाखा, महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर को उनके यू0ओ0नो0 क्रमांक प.10/कारा/लेखा/नि.ले./ड्राफ्ट पैरा/05-06/28411 दिनांक 17.6.08 के संदर्भ में सूचनार्थ।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

परिपत्र
=====

समस्त प्रभाराधिकारी,
कारागृह, एवं उपकारागृह ।

विषय:- बंदियों की निजी सम्पत्ति जो कारागृहों में पड़ी हुई है के
निस्तारण के संबंध में ।

-000-

संदर्भित मामलों में कारागृहों एवं उपकारागृहों से सूचना मांगी जाने पर
विदित हुआ है कि कारागृहों एवं उपकारागृहों पर रिहा हुए बंदियों की निजी
सम्पत्ति काफी मात्रा में काफी समय से पड़ी हुई है, जिसका निष्पादन किया जाना
नितांत आवश्यक है ।

यह तो जेल अधिकारी का कर्तव्य होता है कि कारागार उपकारागार से
मुक्त होते समय बंदी की निजी सम्पत्ति लौटावे । संभवतः इसी कारण राजस्थान,
पिजन्त रूल 1951 के पार्ट 25 सेक्शन 6 में वर्णित नियमों में रिहा हुए बंदियों की
कारागृहों पर जमा निजी सम्पत्ति के निष्पादन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, अतः
ऐसी स्थिति में कारागार विभाग के पास दो ही विकल्प रह जाते हैं §1§ कारागृहों
एवं उपकारागृहों के अभिलेख के आधार पर संबंधित रिहा हुए बंदियों को उनके निवास
पर रजिस्टर्ड पत्र भेजकर अपनी निजी सम्पत्ति वापिस ले जाने के लिये कहा जावे, या
§2§ राजस्थान पिजन्त रूल 1951 के पार्ट-25 के सेक्शन-6 के नियम 180 के अनुसार
रिहा हुए बंदी को मृतक मानकर उसकी निजी सम्पत्ति का निष्पादन किया जावे ।

उक्त 2 विकल्पों में से पहले विकल्प के अनुसार कार्यवाही करना आवश्यक
है अतः समस्त प्रभाराधिकारी कारागृहों एवं उपकारागृहों को आदेश दिये जाते हैं
कि वे अपने से संबंधित कारागृहों एवं उपकारागृहों पर पड़ी रिहा हुए बंदियों की
निजी सम्पत्ति के संबंध में कारागृह अभिलेख में वर्णित उनके निवास के पत्तों पर रजिस्टर्ड
पत्र भेजे जावें । यदि रजिस्टर्ड पत्र भेजे जाने पर भी पहले पत्र के भेजे जाने के पश्चात
एक वर्ष की अवधि में कोई उत्तर बंदी की ओर से प्राप्त नहीं हो तो बंदी की
निजी सम्पत्ति को लावारिश सम्पत्ति मानकर जिलाधीश के माध्यम से निस्तारण
किये जाने की कार्यवाही करें और आप द्वारा संदर्भित मामलों में जो भी कार्यवाही
की जावे । उसकी सूचना इस कार्यालय को दिये जाने का भी विशेष ध्यान रखें ।



ह/-

उप-महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर.